भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2906
मंगलवार, 18 मार्च, 2025/27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

वलसाड में सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण

2906. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात, विशेषकर वलसाड में कितनी सहकारी समितियों को सहकारी समितियों के बीच सहयोग पहल के अंतर्गत डिजिटल बनाया गया है;
(ख) वलसाड की सहकारी समितियों में शासन पारदर्शिता और वित्तीय दक्षता पर डिजिटलीकरण का प्रभाव; और
(ग) ग्रामीण उद्यमियों और किसानों के लिए ऋण सुलभता बढ़ाने हेतु वलसाड में सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख) प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए " सहकार से समृद्धि" के मंत्र के माध्यम से देश में समृद्धि प्राप्त करने के लिए , केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री द्वारा 21 मई, 2023 को गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) में ' सहकारिता में सहकार' को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई ताकि ग्रामीण सहकारी बैंकों के साथ प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (पीडीसीएस) के सभी वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके और सहकारी क्षेत्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। पायलट परियोजना के तहत की गई गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

i. डेयरी सहकारी समितियों को DCCBs का बैंक मित्र बनाया गया: डिजिटल वित्तीय लेनदेन के माध्यम PDCS के व्यवसाय को आसान बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, डोरस्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए नाबार्ड के वित्तीय समावेशन निधि (FIF) के सहयोग से इन बैंक मित्र PDCS को माइक्रो-एटीएम दिए गए थे ।

ii. DCCBs के माध्यम से रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): DCCBs के व्यवसाय और पहुंच का विस्तार करने और डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक तरलता/ ऋण प्रदान करने के लिए, DCCBs द्वारा PDCS के सदस्यों को तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों पर समय पर ऋण प्रदान करने और अन्य वित्तीय लेनदेन को सक्षम बनाने के लिए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी किए गए थे।

iii. अभियान के बारे में वित्तीय साक्षरता शिविरों (FLCs) के माध्यम से जागरूक बनाया गया था, जिसे वित्तीय समावेशन निधि (FIF) के द्वारा सहायता प्रदान की गई थी।

पायलट प्रोजेक्ट के दौरान मिले अनुभवों के आधार पर, अभियान का विस्तार किया गया और 15 जनवरी 2024 से इसे गुजरात के सभी जिलों में लॉन्च किया गया। 'सहकारिता में सहकार' अभियान के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया 19.09.2024 को जारी की गई। राज्यव्यापी अभियान के दौरान उपलब्धियां नीचे दी गई हैं-

- डीसीसीबी द्वारा 2,23,994 से अधिक नए रुपे केसीसी जारी किए गए जिनमें से वलसाड जिले में 2,126 रुपे केसीसी जारी किए गए।
- नए बैंक मित्र पीडीसीएस को 6,446 माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए, जिनमें से वलसाड जिले में 503 माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए।
- वलसाड जिले में 503 सहित कुल 6,529 बैंक मित्र नामांकित किये गये।
- वलसाड जिले में 67,527 सहित 23 लाख से अधिक जमा खाते खोले गए।
- कुल जमा राशि 8,329 करोड़ रुपए जमा किए गए, जिनमें वलसाड जिले में जमा राशि 30 करोड़ रुपए जमा किए गए।

इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित "कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सुदृढ़ीकरण" योजना के तहत, गुजरात राज्य के 5,754 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 22 पैक्स वलसाड जिले से हैं। पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से उनकी शासन पारदर्शिता और वित्तीय दक्षता में सुधार होगा।

(ग) वलसाड में ग्रामीण उद्यमियों और किसानों के लिए ऋण सुलभता बढ़ाने के लिए, डीसीसीबी राज्य के सहकारी समितियों के पंजीयक (आरसीएस) और नाबार्ड की देखरेख में नए उत्पाद विकसित करने, सरकारी प्रायोजित योजना को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) डीसीसीबी के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ताकि उनकी प्रणाली को मजबूत किया जा सके और किसानों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। पीएसीएस/पीडीसीएस को एम-एटीएम का आवंटन और सदस्यों को रुपे कार्ड जारी करने से किसानों के लिए बैंकिंग में आसानी होगी।

*****